भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *199
जिसका उत्तर मंगलवार 22 मार्च, 2022
1 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है

आईडीबीआई बैंक का विनिवेश/निजीकरण

***199 श्रीमती फूलो देवी नेतम:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आईडीबीआई बैंक में अपने शेयरों की बिक्री में अभिरुचि के प्रकटन की माँग करते हुए बोली की प्रक्रिया शुरु कर दी है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण के संबंध में आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों की चिंताओं का निवारण करने हेतु उनकी यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ परामर्श किया है; और
(घ) वित्त मंत्री द्वारा 2003 वर्ष में सदैव कम से कम 51 प्रतिशत की शेयर होल्डिंग बरकरार रखने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बेचने का प्रस्ताव क्यों कर रही है?

उत्तर
वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया है।

*****

'आईडीबीआई बैंक का विनिवेश/निजीकरण' के संबंध में दिनांक 22.03.2022 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *199 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य

(क) एवं (ख) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ भारत सरकार (जीओआई) और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शेयरधारिता का रणनीतिक विनिवेश करने के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के मई, 2021 के अनुमोदन के अनुसरण में, रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करने से पहले निवेशक अभिरूचि का मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान में प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(ग) रणनीतिक बिक्री के लिए निबंधन एवं शर्तों का निर्धारण करते हुए मौजूदा कर्मचारियों और अन्य शेयरधारकों की विधिसम्मत चिंताओं का शेयर खरीद करार (एसपीए) में किए गए उचित प्रावधानों के माध्यम से समुचित तरीके से समाधान किया जाता है।

(घ) केंद्रीय बजट 2016-17 के बजट भाषण में, यह घोषणा की गई थी कि सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम करने के विकल्प पर विचार करेगी। इस घोषणा के अनुसरण में, एलआईसी ने आईआरडीएआई और आरबीआई के अनुमोदन के साथ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में 51% नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। इसके बाद, 2021-22 के बजट भाषण में, आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार की इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश की घोषणा की गई थी और मई, 2021 के सीसीईए के निर्णय के अनुसार, आईडीबीआई बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ भारत सरकार और एलआईसी की शेयरधारिता का रणनीतिक विनिवेश करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रत्याशा की जाती है कि रणनीतिक खरीदार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के वर्धन और व्यावसायिक संभावना के ईष्टतम विकास के लिए निधियों, नई प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटियों का समावेश करेगा और पूंजी के लिए एलआईसी और भारत सरकार पर किसी निर्भरता के बिना और अधिक व्यवसाय को सृजित करेगा। आईडीबाआई बैंक लिमिटेड में भारत सरकार की इक्विटी के रणनीतिक विनिवेश के द्वारा निर्मुक्त संसाधनों का उपयोग सामाजिक क्षेत्र/सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, जिससे नागरिकों को लाभ होगा।

****